

>

Title: Need to fix minimum support price of jute at Rs. 5000/- per quintal.

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये सरकार किसान की बातें करती है, लेकिन केन्द्र सरकार सोई हुई है। देश में 60 परसेंट से ऊपर किसान हैं। इस समय सारा वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ इलाके, असम, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में किसानों की अत्यधिक लाभजनक फसल जूट है। केन्द्र सरकार ने इस बार जो एमएसपी लगाया, उसका रेट इस बार 2300 रुपए विवंटल है, जब कि पिछले साल उसका रेट 2200 रुपए था। क्या केन्द्र सरकार किसानों को भीख दे रही है? जूट उत्पादन का खर्च बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ गया है और लेबर का दाम भी बढ़ गया है। किसान उसे बाजार में बेचने लगे।

अध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार किसानों के लिए जो संस्था है, जिसका नाम जेसीआई है, वह किसानों के हितों के लिए गांव-गांव जाकर किसानों से जूट खरीदे। जो एमएसपी लगाया है, वह बहुत कम है, उसे 2300 रुपए से बढ़ा कर पांच हजार रुपए विवंटल करे।

**अध्यक्ष महोदया:**

श्री महेन्द्र कुमार राय,

डॉ. अनूप कुमार साह,

श्री शक्ति मोहन मलिक,

डॉ. तरुण मंडल श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।